

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 अगस्त 2024—भाद्रपद 08, शक 1946

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 8 जुलाई 2024

क्रमांक ई 1-10/2020/एक-2.—छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2005 आबंटन वर्ष के अधिकारियों को अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति हेतु उपयुक्तता का निर्धारण किये जाने के लिये आयोजित छानबीन समिति की बैठक दिनांक 16-02-2021 में श्री राजेश सुकुमार टोप्पो के संबंध में अपनी अनुशंसा बंद लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था. पूर्णविचार उपरांत राज्य शासन द्वारा श्री टोप्पो की पदोन्नति के संबंध में बंद लिफाफे में की गई अनुशंसा को खोले जाने का निर्णय लिया गया. छानबीन समिति की बैठक दिनांक 16-02-2021 में श्री टोप्पो को अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति के लिये योग्य पाया गया है. अतएव अनुशंसा अनुसार राज्य शासन एतद्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के आबंटन वर्ष 2005 बैच के अधिकारी श्री राजेश सुकुमार टोप्पो को उनसे कनिष्ठ अधिकारी श्री एस. प्रकाश, भा.प्र.से.

(2005) के अधिसमय वेतनमान में देय पदोन्नति दिनांक 01-01-2021 से अधिसमय वेतनमान Pay Matrix Level-14 में पदोन्नत करते हुए सचिव, जल संसाधन विभाग के पद पर पदस्थ करता है। यह पदोन्नति इस शर्त पर दी जाती है, कि वे Mid Career Training (Phase-IV) में अनिवार्य रूप से भाग लेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार बंसल, सचिव।

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 25 जुलाई 2024

शुद्धि पत्र

क्रमांक एफ 1-28-2019/32 पार्ट.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16-12-2022 के पैरा 1 में अंकित प्रविष्टि “विधिक सदस्य” के स्थान पर “न्यायिक सदस्य” पढ़ा जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. तिकी, संयुक्त सचिव।

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 6 अगस्त 2024

क्रमांक एफ /12-2/2020/2104/मबावि/50.—राज्य शासन एतद्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 54 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के नियम 41 के प्रावधानों के तहत समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14-11-2022 को निरस्त करते हुए राज्य स्तरीय निरीक्षण समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन करता है :—

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. आयुक्त/संचालक महिला एवं विकास विभाग एवं पदेन सचिव राज्य बाल संरक्षण समिति | — | अध्यक्ष |
| 2. अध्यक्ष मानव अधिकार आयोग द्वारा नामांकित सदस्य | — | सदस्य |
| 3. अध्यक्ष राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा नामांकित सदस्य | — | सदस्य |
| 4. आयुक्त/संचालक स्वास्थ्य द्वारा नामांकित चिकित्सा अधिकारी/मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ | — | सदस्य |
| 5. बच्चों के अधिकार व संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत एक सामाजिक कार्यकर्ता एवं स्वैच्छिक संगठन का प्रतिनिधि — 1. श्री सत्यनारायण जायसवाल
2. श्री बलराम सोनी | — | सदस्य |
| 6. संबंधित जिले के अध्यक्ष/सदस्य बाल कल्याण समिति | — | सदस्य |
| 7. कार्यक्रम प्रबंधक दत्तक ग्रहण | — | सदस्य |

- यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा तथा इसका कार्यकाल आदेश जारी होने की तिथि से 03 वर्ष के लिए रहेगा।
- यह समिति किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 54 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के नियम 41 के प्रावधानों के अनुसार कार्य संपादित करेगी।
- यह समिति, तीन सदस्यों से अन्यून के एक दल में, जिसमें कम से कम एक महिला होगी और एक चिकित्सा अधिकारी होगा, आर्बिट्रल क्षेत्रों में तीन मास में कम से कम एक बार बालक रखने वाले सुविधा तंत्रों का आज़ापक रूप से निरीक्षण करेंगी और उनके निरीक्षण के एक सप्ताह के भीतर ऐसे निरीक्षण के निष्कर्षों की रिपोर्ट अग्रिम कार्रवाई के लिए, यथास्थिति, जिला बाल संरक्षण ईकाई या राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगी।

4. राज्य निरीक्षण समिति किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 2 की उपधारा (21) में यथा परिभाषित बाल देखरेख संस्थाओं का प्रारूप 46 में निरीक्षण करेगी.
5. राज्य निरीक्षण समिति यह तय करने के लिए कि संस्था देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के लिए है, संस्था में रहने वाले बालकों का यादृच्छिक निरीक्षण करेगी.
6. बालकों का कल्याण सुनिश्चित करने तथा उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए संस्थाओं के भ्रमण के दौरान राज्य निरीक्षण समिति उनसे बातचीत करेगी.
7. राज्य निरीक्षण समिति अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए विभाग के सचिव को रिपोर्ट भेजेगी.
8. राज्य निरीक्षण समिति, अधिनियम के उपबंधों तथा इसके अधीन बनाए गए, नियमों के अनुसार बाल देखरेख संस्थाओं में सुधार और विकास के लिए अनुशंसाएं करेगी तथा इसे उपयुक्त कार्यवाही के लिए राज्य बाल संरक्षण समिति अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई को भेजेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 1 जुलाई 2024

क्रमांक/9447/भू-अर्जन/2024/201805050400061/अ-82/2017-18. —चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	हरदीबाजार	उतरदा प.ह.नं. 11	2.269	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	उतरदा जलाशय योजना के नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत वसंत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

धमतरी, दिनांक 1 अगस्त 2024

प्रकरण क्रमांक 202308130600027/अ-82/2022-23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	बेलरगांव	बोरबांधा प.ह.नं. 40	2.71	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी नगरी, जिला धमतरी.	“बोरबांधा जलाशय का वेस्टवियर निर्माण कार्य”

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, नगरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नम्रता गांधी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 1 जुलाई 2024

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013
की धारा 14 अंतर्गत

क्रमांक/9446/भू-अर्जन/2024/201805050400061/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

प्रकरण में धारा 7 के अधीन विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदन माह जनवरी 2023 में प्रस्तुत किया गया था. उक्त तिथि से आज की तिथि के मध्य, विधानसभा निर्वाचन 2023 एवं लोक सभा निर्वाचन 2024 नियत होने तथा राजस्व अधिकारी कर्मचारियों के निर्वाचन कार्य में संलग्न होने से भौतिक सत्यापन एवं दावा आपत्तियों का निराकरण में विलंब हुआ तथा धारा 11 के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना, धारा 7 के अधीन विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रस्तुत की गई सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट अंकन की तारीख से बाहर मास के भीतर जारी नहीं की जा सकी है.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 14 में वर्णित प्रावधान एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त कार्यवाही हेतु बारह मास की अवधि की वृद्धि की जाती है एवं जनसाधारण हेतु सूचना प्रकाशित/प्रदर्शित की जाती है।

भूमि का वर्णन					धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	ख.नं.	क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कोरबा	हरदीबाजार	उतरदा प.ह.नं. 11	103/6	0.028	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	उतरदा जलाशय योजना के नहर निर्माण कार्य.
			103/8	0.028		
			106/1	0.243		
			106/4	0.263		
			104/2	0.040		
			104/1	0.024		
			104/5	0.040		
			231/1	0.061		
			230/2/क	0.061		
			230/2/ख	0.118		
			234/2	0.061		
			235/11	0.061		
			235/21	0.138		
			235/12	0.053		
			235/5	0.101		
			329/1 घ, 329/2	0.049		
			235/6	0.020		
			235/7	0.021		
			331	0.089		
			332/2, 350/2	0.251		
			405/1	0.049		
			406/2	0.057		
			407/7	0.032		
			407/1	0.032		
			408/3	0.036		
			409/1	0.057		
			411	0.032		
			413/9	0.041		
			413/6	0.041		
			414/5	0.020		
			403/6	0.061		
			403/3/1 से	0.061		
योग		32 खसरे	2.269			

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत वसंत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

बिलासपुर, दिनांक 30 जुलाई 2024

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2014-15/2595.— उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग कोटा जिला बिलासपुर द्वारा ग्राम छतौना, प.ह.नं. 37 तहसील सकरी, जिला-बिलासपुर स्थित निजी भूमि कुल रकबा 0.02 एकड़/0.010 हेक्टेयर भूमि को अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के तहत नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 प्रारंभिक अधिसूचना तथा धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमशः दिनांक 14-08-2015 तथा दिनांक 01-07-2016 को कराया गया है।

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग कोटा के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही हेतु सम्मिलित उक्त भूमि खसरा क्रमांक 1077/2 रकबा 0.02 एकड़/0.010 हेक्टेयर भूमि पूर्व में अर्जन किया जा चुका है। फलस्वरूप भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा-93 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है।

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम - छतौना तहसील सकरी जिला बिलासपुर

क्रमांक	खसरा नंबर	रकबा
01	1077/2	0.02 एकड़ / 0.010 हेक्टेयर

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा जिला बिलासपुर छ.ग. के कार्यालय में देखा जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनीश कुमार शरण, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला-सक्ती, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग**

सक्ती, दिनांक 1 अगस्त 2024

क्रमांक/296/भू.अ./2024.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-सक्ती
- (ख) तहसील-हसौद
- (ग) नगर/ग्राम-चिस्दा, प.ह.नं. 33
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.397 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
67/4	0.012
67/3	0.012
58	0.045

(1)	(2)	अनुसूची	
67/2	0.012	(1) भूमि का वर्णन-	
64/2	0.014	(क) जिला-कोरबा	
96/1	0.016	(ख) तहसील-कटघोरा	
92/2	0.008	(ग) नगर/ग्राम-झोरा	
91/1	0.024	(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.890 हेक्टेयर	
92/1	0.053	खसरा नम्बर	रकबा
90/1	0.057		(हेक्टेयर में)
90/4	0.012	(1)	(2)
82/2	0.000	19/1	0.040
82/4	0.000	19/2	0.040
83/1	0.020	142/33	0.024
2340/2	0.000	102/2, 101/4	0.061
2341	0.032	103/1, 104/1	0.016
2340/3	0.016	103/2, 104/2	0.016
2343/2	0.028	103/3, 104/3	0.016
2340/5	0.004	103/4, 104/4	0.016
2326/12	0.020	103/5, 104/5	0.008
2327/2, 2327/3	0.008	105	0.008
2326/7, 2326/8	0.004	107/1	0.061
योग	22	107/2	0.061
	0.397	107/3	0.061
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बसंतपुर परसदा-घोघरी मार्ग निर्माण हेतु.		110	0.121
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.		111/1	0.057
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,		164/1	0.032
अमृत विकास तोपनो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.		164/2	0.036
		180	0.106
		197/2	0.065
		198/1	0.036
		198/2	0.077
		198/3	0.032
		198/4	0.036
		199/2	0.016
		200	0.012
		202/1	0.044
		182/1	0.032
		202/2	0.032
		182/2	0.020
		202/3	0.028
		182/3	0.036
		202/4	0.024
		182/4	0.036
		181	0.016
		142/6/छ	0.202
		204/1	0.028
		142/1 में से	0.040

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 5 अगस्त 2024

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202206050400002/अ-82/2021-22/11034. — चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

(1)	(2)	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-झोराघाट-कोड़ियाघाट मार्ग में हसदेव नदी पर उच्चस्तरीय पुल सेतु के पहुँच मार्ग हेतु.
142/15	0.061	
142/1 में से	0.040	
142/1 में से	0.021	
142/1 में से	0.121	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
142/1 में से	0.040	
142/6 में से	0.024	
योग	39	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजीत वसंत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 19th July 2024

No. 738/Confdl./2024/II-2-09/2024.—In view of the direction of Hon,ble Supreme Court dated 19-05-2023 issued in W.P. (Civil) No. 643/2015 (All India Judges Association & Ors. Vs. Union of India), relating to revision of norms for grant of Assured Career Progression (ACP) Scale, the High Court of Chhattisgarh, hereby prescribes following norms for grant of ACP Scale to Civil Judge Junior Division and Civil Judge Senior Division :—

General norms for grant of Assured Career Progression Scale

A Civil Judge Junior Division or a Civil Judge Senior Division shall be entitled to be considered for conferment of Assured Career Progression Scale if :—

- He has not been promoted due to non-availability of promotional post;
- The High Court finds him fit to be conferred with Assured Career Progression Scale.
- There is no conclusive adverse report at regards integrity and honesty.

Norms for grant of ACP-I and ACP-II to Civil Judge Junior Division :—

- (A). A Civil Judge Junior Division on the basis of overall preformance in the ACR has been graded :—

In case of ACP-I	Atleast three “C” during past 5 years and has not been graded “E” more than once during that period.
In case of ACP-II	Atleast one “B” and two “C” and has not been graded “E” even once during past 5 years after grant of First Assured Career Progression Grade.

Provided further that where the probation period of Civil Judge Junior Division is extended, the grant of First Assured Career Progression Scale shall be deferred proportionately to commensurate with the extended probation period.

- A Civil Judge Junior Division shall not be denied the benefits of ACP Scale unless the work done in terms of disposal by the concerned Officer is not consistently poor/un-satisfactory.
- That if the work done in terms of average units per day earned by the concerned Officer for a continuous period of five years commencing from any year after he/she gets the First Assured Career Progression Scale, on yearly basis, falls within “Good” category as per the norms fixed in this respect by the High Court, the Officer shall not be denied the benefits of ACP.

Norms for grant of ACP-I and ACP-II to Civil Judge Senior Division :—

(A). A Civil Judge Senior Division on the basis of overall performance in the ACR has been graded :—

In case of ACP-I	Atleast one “B” and two “C” during past 5 years after being promoted as <i>Civil Judge Senior Division</i> and has not been graded “E” even once during that period.
In case of ACP-II	Atleast three “B” and has not been graded “D” twice and has not been graded “E” even once during past 5 years after grant of First Assured Career Progression Grade.

(B). That, if the work done in terms of average units per day earned by the concerned Officer for a continuous period of five years commencing from any year after he gets promoted as Civil Judge Senior Division, on yearly basis, falls within “Good” category as per the norms fixed in this respect by the High Court, the Officer shall not be denied the benefits of ACP.

GENERAL INSTRUCTIONS

(1) The requirement as to grading in terms of average units per day can be relaxed by the Sub-Committee upon considering the explanation offered by the Officer concerned, in the following situations :—

(a) If it is found that the average pendency of regular Civil/Criminal cases per month during the year was less than 350 cases in the relevant year ;

or

(b) If it is found that the Officer was holding exclusive Special Courts for the CBI cases or Negotiable Instruments Act, 1881 cases or Commercial Courts Act cases or Juvenile Justice Act cases or Domestic violence Act cases or MP/MLA cases or Economic Offence cases or was engaged in Administrative responsibilities like Secretary, DLSA/SLSA or on deputation or was discharging any other obligation of the nature so as to substantially reduce his average working hours per day.

Explanation regarding lesser disposal must be submitted by the Judicial Officer to the High Court in terms of the *Registry Circular No. 4972/III-1-3/2002 dated 13-04-2022 (copy enclosed)*.

(2) Adverse remarks in the ACR shall be taken into consideration for assessing the performance for grant of ACP.

(3) Any other remarks made with regard to behavior, conduct etc, may also be taken into consideration after affording an opportunity to the concerned Officer to offer his/her explanation about the same.

(4) No Judicial Officer shall be entitled to get the benefit of First Assured Career Progression Scale or Second Assured Career Progression Scale, if

(a) more than once warning or caution is issued against him;

Note :— Mere “advice” would not amount to “warning” or “caution”;

(b) in case, an Officer is undergoing punishment period as contemplated under Rule 10 of Chhattisgarh Civil Service (Classification, Control and Appeal), Rules, 1966, he/she shall be treated as “Not fit for grant of ACP” during such period, the punishment is in force.

(c) for any other reason the High Court finds him unfit to be conferred with First Assured Career Progression or Second Assured Career Progression.

- (5) (a). At the time of consideration of the cases of Judicial Officers for grant of First or Second Assured Career Progression Scale, details of Judicial Officers in the consideration zone falling under the following categories should be specifically brought to the notice of the Sub-Committee :—
- In the matters, where the Competent Authority has taken decision in the file to initiate Departmental Enquiry;
 - Judicial Officers under suspension;
 - Judicial Officers in respect of whom a charge-sheet has been issued and the disciplinary proceedings are pending; and
 - Judicial Officer in respect of whom prosecution for a criminal charge is pending.
- (b). *Sealed cover procedure.*— The Sub-Committee shall assess the suitability of the Judicial Officers coming within the purview of the circumstances mentioned above along with other eligible candidate without taking into consideration the disciplinary case/criminal prosecution pending. The assessment of the Sub-Committee, will be kept in a sealed cover. The cover will be superscribed “findings regarding suitability for grant of First/Second Assured Career Progression Grade to the grade/post of in respect of Shri/Smt./Ku..... (name of the Judicial Officer). Not to be opened till the termination of the disciplinary case/criminal prosecution against Shri/ Smt./Ku.....”. The proceedings of the Sub-Committee need only contain the note “The findings are contained in the attached sealed cover”.
- (c). *Procedure by subsequent Sub-Committees.*— The same procedure outlined in clause (b) above will be followed by the subsequent Sub-Committee convened till, the disciplinary case/criminal prosecution against the Judicial Officers concerned is concluded.
- (d). On conclusion of Departmental Enquiry or the criminal case, as the case may be, if delinquent is exonerated/acquitted, the sealed cover shall be opened and recommendation of Sub-Committee shall be acted upon from the date of entitlement.
- (6) Process of grant of ACP would normally be initiated 3 months in advance from the date on which the Judicial Officers would be completing 5/10 years of service and the financial benefits would be paid to the Judicial Officer within 6 months after the Judicial Officer steps into 6th/11th year of service. If for any reason, delay in grant of ACP goes beyond one year, one additional increment for every year shall be granted subject to adjustment while drawing the arrears on grant of ACP.

Bilaspur, the 19th July 2024

No. 11250/Checker/III-6-2/2007 (Pt.-I).—In exercise of the powers Conferred under clause (b) of sub-section (1) of Section 283 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, the High Court of Chhattisgarh hereby specially empowers the following Judicial Magistrate First Class to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section :—

Sl. No.	Name of the Judicial Magistrate First Class	Present place of posting	Civil District
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ku. Pranjali Netam, J.M.F.C., Ambikapur	Ambikapur	Sarguja (Ambikapur)
2.	Ku. Swarna Dehare, J.M.F.C., Surajpur	Surajpur	Surajpur

By order of the High Court,
BALRAM PRASAD VERMA, Registrar General.

Bilaspur, the 11th July 2024

No. 52/L.G./2024/II-3-27/2007.—Smt. Neeta Yadav, Principal District & Sessions Judge, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 03 days from 02-05-2024 to 04-05-2024 along with permission to remain out of headquarter.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Yadav, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 11th July 2024

No. 53/L.G./2024/II-2-28/2018.—Shri Jaideep Garg, Special Judge (Atrocities), Korba is hereby, granted earned leave for 15 days from 01-04-2024 to 15-04-2024 along with permisison to remain out of headquarters and commuted leave for 04 days from 29-04-2024 to 02-05-2024 along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Garg, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 162 days of earned leave and 194 days of half-pay-leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 11th July 2024

No. 54/L.G./2024/II-2-24/2016.—Shri Alok Kumar, I Additional Principal Judge, Family Court, Durg is hereby, granted earned leave for 06 days from 29-04-2024 to 04-05-2024 along with permission to remain out of headquarters after the office hours of 27-04-2024 till before the office hours of 06-05-2024.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Kumar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 11th July 2024

No. 55/L.G./2024/II-2-10/2016.—Shri Santosh Kumar Tiwari, Judge, Family Court, Dakshin Bastar (Dantewara) is hereby, granted earned leave for 04 days from 15-04-2024 to 18-04-2024 along with permission to remain out of headquarters from 13-04-2024 to 18-04-2024.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Tiwari, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 183 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 11th July 2024

No. 56/L.G./2024/II-2-28/2022.—Smt. Geeta Neware, Judge Family Court, Jashpur is hereby, granted earned leave for 05 days from 06-05-2024 to 10-05-2024 along with permission to remain out of headquarters from 05-05-2024 to 12-05-2023.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Neware, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 298 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 11th July 2024

No. 57/L.G./2024/II-3-7/2008.—Smt. Vinita Warner, Judge, Family Court, Rajnandgaon is hereby, granted earned leave for 03 days from 10-06-2024 to 12-06-2024.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Warner, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 11th July 2024

No. 58/L.G./2024/II-3-30/2007.—Shri Onkar Prasad Gupta, Judge Family Court, Korba is hereby, granted earned leave for 03 days from 02-06-2024 to 04-06-2024 in continuation of summer vacation along with permission to remain out of headquarters from 26-05-2024 to 04-06-2024.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Gupta, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+12 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
AWADH KISHORE, Additional Registrar (ADMN.)